

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 29 अक्टूबर, 2009

विषय:- वित्तीय वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-73 के किमी 0 1-4 पर स्वीकृत कार्यों हेतु यूटीलिटी शिफ्टिंग के कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-871/42 रा.मा.नि.-2/2008 दिनांक 26मई, 2009 एवं संख्या-1308/42 रा०म०-नि०-2/09 दिनांक 12.8.2009 द्वारा उपलब्ध कराये गये यूटीलिटी शिफ्टिंग कार्यों के आगणनों के संदर्भ में एवं पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के शासनादेश संख्या- 12014/199/2008-यू.आर.-एन.एच.-11 दिनांक 2.2.2009 द्वारा जारी प्रदत्त स्वीकृति आदेश के साथ संलग्नक तनकीकी नोट के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये यूटीलिटी शिफ्टिंग कार्यों के आगणन रुपये 232.92 लाख पर टी०ए०सी० वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त आंकलित धनराशि रुपये 225.57 लाख (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख सतावन हजार मात्र) की संलग्न सूची के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2009-10 में रु० 10.00 लाख (रु० दस लाख मात्र) के व्यय किये जाने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भौति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।
7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद का व्यय दूसरी मद में कदापि न किया जाये।
8. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

: 2:

10. जी0पी0 डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित कराना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड चसूल किया जायेगा।
11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
12. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश सं0-2047/XIV-219/06 दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जायेगा।
13. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
14. यह आदेश वित्त विभाग अनुभाग-2 के अशासकीय संख्य-यू0ओ0-213/XXVII(2) 2009 दिनांक 29 सितम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या-4052/111(2)/05, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी हरिद्वार।
5. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निर्देशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अधीक्षण अभियन्ता, दसवां राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त लोक निर्माण विभाग देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
प्रदीप
(महिमा)

4052

शासनादेश संख्या- / 111(2)/09-08(प्रा.आ.)/09 दिनांक 9 अक्टूबर, 2009 का संलग्नक।

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	टी०ए०सी० वित्त द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2009-10 में व्यय की अनुमति
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-73 के किमी० 1 से 4 में दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण कार्य के अन्तर्गत यूटीलिटी (वाटर सप्लाई/सीवर लाईन) शिफ्टिंग का कार्य ।	133.42	131.26	5.00
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-73 के किमी० 1 से 4 में दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण कार्य के अन्तर्गत यूटीलिटी (इलेक्ट्रिक लाईन) शिफ्टिंग का कार्य ।	99.50	94.31	5.00
	योग:-	232.92	225.57	10.00

(रु० दस लाख मात्र)

प्रदीप सिंह रावत

उप सचिव।